विचार बिन्दु

ख्याति वह प्यास है जो कभी नहीं बुझती। अगस्त्य ऋषि की तरह वह सागर को पीकर भी शांत नहीं होती। –प्रेमचंद

सोशल मीडिया: वरदान भी, अभिशाप भी!

वर्तमान समय सोशल मीडिया के प्रभुत्व का समय है। यह बहुत पुरानी बात नहीं है जब मीडिया के नाम पर केवल समाचार पत्र, फिर रेडियो और उसके बाद सरकारी टेलीविज़न हमें उपलब्ध थे। बाद में टेलीविज़न के निजी चैनल भी आए। लेकिन इन सब पर किसी न किसी तरह का नियंत्रण होता था। अखबार में वही छपता था जो संपादक चाहता था और इसी तरह अन्य दृश्य श्रव्य माध्यमों में भी सामग्री पर्याप्त छानबीन के बाद ही प्रसारित हो पाती थी। लेकिन पिछले दशक तक आते–आते यह परिदृश्य बदल गया। दुनिया में और भारत में भी इंटरनेट के प्रसार और स्मार्ट फोन की व्यापक पहुंच के कारण फ़ेसबुक, एक्स (पुराना नाम – ट्विटर), इंस्टाग्राम, यू ट्यूब, ब्ल्यूस्काय, थ्रेड्स, और वॉट्सएप जैसे अनेक प्लेटफॉर्म्स हम सबकी पहुंच में आ गए और करोड़ों लोगों के लिए यह संभव हो गया कि वे औरों तक अपनी बात, बिना किसी अवरोध और नियंत्रण के पहुंचा सकते हैं। और जब बात पहुंचाना संभव हुआ तो स्वभावतः वह बात जनमत को प्रभावित भी करने लगी। याद करें, पहले यह सुविधा केवल सांस्थानिक माध्यमों जैसे अख़बार, रेडियो, टेलीविज़न आदि को ही सुलभ थी, अब हम में से हरेक व्यक्तिगत रूप से ऐसा करने की सामर्थ्य पा गया।

इस बदलाव ने जो सबसे बड़ा काम किया वह है सूचना का लोकतंत्रीकरण। कल तक जो काम केवल पत्रकार और विशेषज्ञ ही कर पा रहे थे अब वह काम आम लोग भी करने लग गए। दूसरा काम यह हुआ कि सूचनाओं का तुरंत प्रसार होने लगा। पहले चौबीस घण्टे में एक बार अखबार आता था या निर्धारित समय पर रेडियो अथवा टेलीविज़न समाचार प्रसारित करते थे। अब यह काम सातों दिन और चौबीसों घण्टे होने लगा। इधर कोई घटना घटित होती है और तुरंत वह सोशल मीडिया मंचों पर फैल जाती है। तीसरी बड़ी बात यह हुई कि पहले जो संवाद लगभग एक तरफा था अब वह बहुपक्षीय हो गया। किसी भी बात पर हममें से कोई भी प्रतिक्रिया दे सकता है, सवाल पूछ सकता है, खंडन या समर्थन कर सकता है। इन तीनों बातों की वजह से सोशल मीडिया माध्यमों ने जनमत निर्माण की प्रक्रिया को सहज, सरल और जीवंत बना दिया है।

इन सब बातों का मिला–जुला असर यह हुआ कि हमारा लोकतंत्र अधिक सहभागी बन गया। सांस्थानिक संचार माध्यमों पर भले ही सरकारें थोड़ा या बहुत नियंत्रण कर लें, सोशल मीडिया के प्लेटफॉम्स पर वे चाहकर भी बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं कर पा रही हैं। इसलिए इन प्लेटफॉर्म्स पर लोग बहुत खुलकर अपनी बात कहते हैं। यह खुलापन लोकतंत्र को सुदृढ़ करता है, भले ही सत्ता को यह नागवार गुज़रे। पारंपरिक सांस्थानिक मीडिया की अपनी सीमाएं होती हैं और उसके अपने स्वार्थ भी बहुत सारी बातों के प्रकटीकरण में बाधक बनते हैं। वे सब बातें सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ पाती हैं। अब यही देखें कि अगर कोई व्यवसाय अख़बारों को भारी विज्ञापन देता है तो वे अखबार उस उत्पादक के बारे में कुछ भी प्रतिकूल प्रकाशित करने से बचते हैं। इसी तरह बहुत सारी सरकारें अपने विरुद्ध कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती हैं और अपने विरुद्ध उठने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए विज्ञापन रोकने जैसे मुलायम या अन्य कर्कश तौर तरीकों का बेझिझक इस्तेमाल करती हैं। इसकी परिणति यह होती है कि बहुत सारी चीज़ें बाहर आ ही नहीं पाती हैं। उन दबी कुचली छिपी चीज़ों को सोशल मीडिया बहुत सहजता से सामने ले आता है। यह सब करते हुए सोशल मीडिया सशक्त विपक्षी की भूमिका तो निबाहता ही है, वह संस्थाओं और सत्ता की निरंकुशता पर भी कुछ नियंत्रण रख पाता है। सोशल मीडिया की एक और बड़ी भूमिका संकट काल के समय सामने आती है। कोविड महामारी की विभीषिका को हम अभी तक भूले नहीं हैं। उस विकट समय में सोशल मीडिया ने ऑक्सीजन, दवाइयों, अस्पताल सुविधाओं और भोजन की उपलब्धता विषयक जानकारियों का प्रसार कर अपनी सार्थकता मनवाई थी। अब भी समय–समय पर यथावश्यकता वह ऐसा करता है।

सोशल मीडिया एल्गोरिद्म आधारित है इसके कारण यह आपको वैसी सामग्री दिखाता है जैसी आप बार-बार देखते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि आप केवल वही देखते-सुनते हैं जो आपकी पसंद का है। उससे भिन्न चरित्र वाली सामग्री आप तक पहुंच ही नहीं पाती है। कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया आपको एक ईकोचेम्बर में ले जाता है जहां आप केवल और केवल अपनी अनुगूंज सुनते हैं। यह बहुत नुकसानदेह है।

लेकिन इस सब से यह न मान लिया जाए कि सोशल मीडिया का केवल उजला पक्ष ही है। इसके अपने ख़तरे भी कम नहीं हैं। एक तो क्योंकि यहां किसी भी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है इसलिए मिथ्या, त्रुटिपूर्ण या द्वेषपूर्ण समाचारों और सूचनाओं के प्रसार का खतरा हमेशा बना रहता है। बहुत बार लोग सबसे पहलेके चक्कर में ऐसी सूचनाएं भी यहां पोस्ट कर देते हैं जो बाद में मिथ्या साबित होती हैं। दुर्भावनावश भी बहुत कुछ अनुचित यहां प्रकट होता रहता है। चुनाव, सांप्रदायिक तनाव आदि के समय प्रायः यह देखने को मिलता है कि निहित स्वार्थी तत्व इन प्लेटफॉर्म्स का अनुचित उपयोग कर लेते हैं। ख़ुद सरकार भी इस बात से भली–भांति परिचित है अतः संकट की ज़रा–सी आहट होते ही वह पहला काम इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का करती है। लेकिन ऐसा करके वह जहां एक समस्या को नियंत्रित करती है, अन्य अनेक समस्याओं को पैदा भी कर देती है। आज का समय ऐसा है जहां न जाने कितने ज़रूरी कामों के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है। उसे बंद करके वे सारे ज़रूरी काम रोक दिये जाते हैं जिसकी वजह से जन समस्याओं में वृद्धि होती है।

इसी क्रम में डीप फेक और तकनीकी छल की भी बात कर ली जानी चाहिए। तकनीक ने ऐसी बहुत सारी सुविधाएं भी दे दी हैं जिनका दुरुपयोग करके मनचाहे परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। अब किसी का भी नकली वीडियो तैयार कर जनमत को भड़काया जाना या उस व्यक्ति विशेष की छवि को धूमिल करना सम्भव हो गया है। आप किसी के चेहरे की, उसके हाव भाव की, उसकी आवाज़ की हूबहू नकल करके वह सब कहला सकते हैं जो असल में वह कभी भी न कहेगा या कहेगी। ऐसा आए दिन होता रहता है।

सोशल मीडिया क्योंकि लगभग नियंत्रण विहीन है इसलिए लोग अपशब्दों के लिए, अपने प्रतिपक्षियों को डराने–धमकाने के लिए और उनकी आवाज़ को दबाने के लिए भी इसका उपयोग करने लगे हैं। बहुत सारे राजनीतिक दलों ने तो बाकायदा ट्रोल आर्मी इस काम के लिए रख रखी है। आप उनके खिलाफ कुछ कहें, वे सारी मर्यादाओं को ताक पर रखकर आप पर पिल पड़ेंगे। इनके शिकार महिलाएं और अल्प संख्यक अधिक होते हैं। कल जो काम लठैत करते थे वही काम अब ट्रोल करने लगे हैं। इस प्रवृत्ति के चलते लोकतांत्रिक संवाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को गहरा आघात पहुंच रहा है।

यहीं एक तकनीकी बात की तरफ भी ध्यान आकर्षित कर लेना ज़रूरी है। सोशल मीडिया एल्गोरिद्म आधारित है इसके कारण यह आपको वैसी सामग्री दिखाता है जैसी आप बार–बार देखते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि आप केवल वही देखते–सुनते हैं जो आपकी पसंद का है। उससे भिन्न चरित्र वाली सामग्री आप तक पहुंच ही नहीं पाती है। कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया आपको एक ईकोचेम्बर में ले जाता है जहां आप केवल और केवल अपनी अनुगूंज सुनते हैं। यह बहुत नुकसानदेह है। भिन्न मत को आप जान ही नहीं पाते हैं और धीरे–धीरे आप इस ग़लतफहमी के शिकार होने लगते हैं कि सारी दुनिया एक ही दिशा में सोच रही है। और जब हम बात तकनीक की कर रहे हैं तो यह भी कहते चलें कि सोशल मीडिया पर हमारी जो बहुत सारी निजी जानकारियां होती हैं उनके दुरुपयोग की आशंकाएं भी कम नहीं हैं।

आप चाहे इसके पक्ष में हों या विपक्ष में, यह मानना पड़ेगा कि आज हमारे जीवन, सोच, विचार और राजनीति पर सोशल मीडिया का बहुत प्रभाव है और यह प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस प्रभाव में काफी कुछ सकारात्मक है तो उतना ही नकारात्मक और नुकसानदायक भी है। हम देखते हैं कि हमारी राजनीति तो अब लगभग सोशल मीडिया पर ही केंद्रित होती जा रही है। जिन दलों के पास साधन हैं वे इसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं और उन्हें इसका लाभ भी मिल रहा है। वे न केवल अपने प्रचार अभियान यहां चलाते हैं, अपने नैरेटिव भी वे सेट करने लगे हैं। और केवल राजनीतिक दल ही क्यों, हम नागरिक भी इन माध्यमों की वजह से अधिक राजनीतिक हुए हैं। हम भी अपनी बात कहने लगे हैं। हां, हममें से बहुतों के अविवेक की वजह से यही सोशल मीडिया कटुता का प्रसारक भी बना है। दोस्तियां और रिश्ते आहत हुए हैं।

इस बात को समझा जाना ज़रूरी है कि कोई माध्यम न पूरी तरह अच्छा होता है और न पूरी तरह बुरा। सब कुछ उसे बरतने वाले पर निर्भर करता है। आप चाकू से सब्ज़ी भी काट सकते हैं और किसी को घायल भी कर सकते हैं। जो विवेकवान हैं वे सोशल मीडिया का सही उपयोग करते हैं और जो वैसे नहीं हैं वे या तो उसका दुरुपयोग करते हैं और या फिर उसी के जाल में कैद होकर रह जाते हैं। वे अपने स्तर पर तथ्यों की पड़ताल करने की बजाय जो उन्हें परोसा जाता है उसी को अंतिम सत्य मानकर तदनुसार अपनी प्रतिक्रिया देते और बर्ताव करते हैं। ऐसे भोले लोगों को विवेक सम्पन्न बनाना हमारे समय की बड़ी चुनौती है।

–अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

राजभवन से लोकभवन : नाम बदला, अब लोकतांत्रिक व्यवहार की बारी

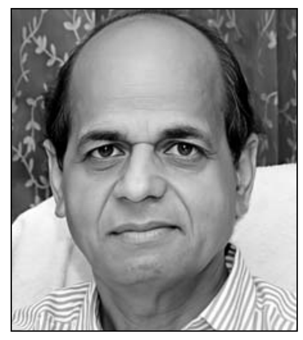

डॉ. कैलाश चन्द सैनी

विलियम शेक्सपियर का प्रसिद्ध कथन 'नाम में क्या रखा है?' साहित्य की दृष्टि से भले ही एक भावनात्मक प्रश्न हो, लेकिन लोकतंत्र और शासन के संदर्भ में नाम का अर्थ बहुत गहरा होता है। नाम केवल पहचान ही नहीं, सोच की दिशा, सत्ता का चरित्र और संस्थागत मंतव्य भी स्पष्ट करता है। जब किसी संस्था का नाम बदला जाता है, तो उससे जुड़े उद्देश्य, अपेक्षाएँ और जवाबदेही भी नए सिरे से परिभाषित होती हैं।

हाल ही में राजस्थान के राजभवन का नाम बदलकर लोकभवन किया गया है।

'राजभवन' का 'लोकभवन' में रूपांतरण केवल शब्दों का बदलाव नहीं, बल्कि यह घोषणा है कि सत्ता के केंद्र में अब 'राज' नहीं, 'लोक' रहेगा। इस परिवर्तन की असली कसौटी यही है कि क्या यह परिवर्तन केवल नाम तक सीमित रहेगा या फिर लोकभवन अपने कार्य–व्यवहार से भी 'लोक' का विश्वास अर्जित करेगा। यह महज़ एक नाम–परिवर्तन नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की ओर लौटने और संवैधानिक संस्थाओं को अधिक जन–केंद्रित स्वरूप देने का प्रतीकात्मक प्रयास है। 'राज' से 'लोक' की ओर यह यात्रा उस अवधारणा को रेखांकित करती है, जिसमें सत्ता का वास्तविक केंद्र शासक नहीं, बल्कि नागरिक होते हैं। ब्रिटिश राज के दौरान राज्यों में पदस्थापित गवर्नर के आवास को 'गवर्नर हाउस' के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि आज़ादी के बाद पहले गवर्नर जनरल सी. राजगोपालाचारी ने इन आवासों को 'राजभवन' नाम दिया था। राजभवन शब्द भारतीय जनमानस में लंबे समय तक औपनिवेशिक शासन, रियासती परंपराओं, सामंती सोच और प्रशासनिक दूरी की स्मृतियों से जुड़ा रहा है। ऐसे में इस बदलाव को लोकतंत्र की मूल भावना – जन–भागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के अनुरूप माना जा सकता है। किंतु यह भी निर्विवाद रूप से सत्य है कि किसी संस्था का नाम बदल जाने मात्र से उसका चरित्र, सोच और कार्यशैली परिवर्तित नहीं हो जाती। यदि लोकभवन के भीतर वही पुरानी मानसिकता, दूरी, औपचारिकता और प्रशासनिक जड़ता बनी रही तो यह परिवर्तन केवल अभिलेखों, साइनबोर्डों और पत्र–व्यवहार तक सीमित होकर रह जाएगा। यह निर्णय एक राष्ट्रीय पहल के तहत लिया गया है। नई दिल्ली में 2–3 अगस्त 2024 को हुए राज्यपालों के सम्मेलन में गठित उप–समिति ने यह महत्वपूर्ण सिफारिश की थी कि देश के समस्त राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में राजभवन और राजनिवास जैसे औपनिवेशिक प्रतीकात्मक नामों को परिवर्तित कर 'लोकभवन' या 'लोक निवास' जैसे जनोन्मुखी नाम दिए जाएँ। इसके बाद 25 नवम्बर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आधिकारिक दिशा–निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैण्ड, छत्तीसगढ, उत्तराखंड, झारखण्ड, केरल और जम्मू–कश्मीर आदि राज्यों ने इस सिफारिश को लागू भी कर दिया। राजस्थान में भी यह परिवर्तन 1 दिसंबर 2025 से औपचारिक रूप से प्रभावी हो गया है। अब राज्यपाल सचिवालय से जुडे सभी आधिकारिक पत्राचार, वेबसाइटों, सरकारी पट्टिकाओं और दस्तावेज़ों में 'लोकभवन' नाम अंकित किया जा रहा है। यह बदलाव निस्संदेह प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन लोकतांत्रिक ढाँचे में इसे तभी वास्तविक परिवर्तन माना जाएगा, जब यह नया नाम प्रशासनिक व्यवहार, कार्य–संस्कृति और नागरिक संवाद की प्रकृति में भी परिलक्षित होगा। राजस्थान पहले भी ऐसे प्रतीकात्मक सुधारों का साक्षी रहा है। 26 अगस्त 2014 को 'महामहिम राज्यपाल' संबोधन को बदलकर 'माननीय राज्यपाल' के रूप में प्रयुक्त किया गया। यह निर्णय तत्कालीन राज्यपाल श्री कल्याण सिंह की पहल पर हुआ और इसने औपनिवेशिक मानसिकता के एक और अवशेष को समाप्त किया गया। इससे पहले भी राज्य के राज्यपाल श्री निर्मल चंद जैन, श्री अंशुमान सिंह, श्री मदनलाल खुराना तथा श्री कलराज मिश्र ने अपने–अपने कार्यकाल में राजभवन को अधिक लोकतांत्रिक, संवादपरक और जन–सुलभ बनाने की दिशा में अनेक प्रयास किए। किसी ने शाही प्रतीकों को हटवाया, किसी ने जन–सुनवाई को बढ़ावा दिया, तो किसी ने सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए भवन को सुलभ बनाया। ये उदाहरण स्पष्ट संकेत हैं कि लोकतंत्र का वास्तविक विस्तार केवल नाम और प्रतीकों से नहीं, बल्कि व्यवहारगत बदलावों से होता है। राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए 'लोकभवन' नाम का महत्व और भी बढ़ जाता है। सदियों तक यहाँ का समाज रियासतों, राजघरानों और सामंती परंपराओं से प्रभावित रहा है। 'राजभवन' शब्द अपने आप में प्रभुत्व, सत्ता और प्रशासनिक दूरी का भाव अभिव्यक्त करता रहा है। इसके विपरीत 'लोकभवन' समानता–आधारित संवैधानिक व्यवस्था का संकेत देता है, जहाँ नागरिक केंद्र में होते हैं। यह अपेक्षा केवल नाम के आधार पर पूरी नहीं हो सकती। जब तक भवन का वातावरण, उसकी नीतियाँ, प्रक्रियाएँ और जनता से संवाद की शैली लोकतांत्रिक संवेदनशीलता से युक्त नहीं होंगी, तब तक 'लोकभवन' का वास्तविक अर्थ अधूरा ही रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या केवल नाम बदल जाने से राजभवन की कार्यप्रणाली स्वतः बदल जाएगी? अनुभव यही बताता है कि व्यवहार, मानसिकता और प्रशासनिक संस्कृति का परिवर्तन किसी आदेश या अधिसूचना से नहीं होता। इसके लिए निरंतर प्रयास, संस्थागत प्रतिबद्धता और नेतृत्व की स्पष्ट इच्छा–शक्ति चाहिए।

लोकभवन का वास्तविक स्वरूप तब उभरेगा, जब राज्यपाल सचिवालय की कार्यशैली अधिक खुली, संवेदनशील और उत्तरदायी बनेगी; जब आम नागरिक की पहुँच वहाँ सहज होगी; जब प्रोटोकॉल की कठोरता संवाद में बाधा नहीं बनेगी; और जब यह भवन केवल औपचारिक कार्यक्रमों का नहीं, बल्कि जन–संवाद, जन–समस्याओं और सामाजिक सरोकारों का केंद्र बनेगा। लोकतांत्रिक व्यवहार में परिवर्तन के लिए लोकभवन में नियमित जन–सुनवाई, विभिन्न सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधि समूहों से संवाद, सामाजिक संगठनों के साथ सतत चर्चा तथा युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचित वर्गों के लिए विशेष संवाद सत्र आयोजित होने चाहिए। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं; उनके माध्यम से लोकतांत्रिक संवाद की संस्कृति को व्यापक स्वरूप मिल सकता है। इसी तरह, कार्य–संस्कृति में पारदर्शिता और जवाबदेही को संस्थागत रूप देना भी अनिवार्य है। राज्यपाल सचिवालय के निर्णयों, कार्यक्रमों और गतिविधियों की अद्यतन जानकारी सार्वजनिक हो। वेबसाइटों, वार्षिक प्रतिवेदनों और संवाद माध्यमों से यह स्पष्ट दिखाई देना चाहिए कि लोकभवन वास्तव में 'लोक' के प्रति उत्तरदायी है। भवन का उपयोग भी केवल औपचारिक और प्रोटोकॉल–केंद्रित न रहकर शिक्षा, संस्कृति, संविधान–जागरूकता, युवाओं के विकास, नवाचार और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों के लिए होना चाहिए। इससे लोकभवन का चरित्र वास्तविक अर्थों में जनता का बनेगा। इसके साथ–साथ लोकभवन का वातावरण, प्रतीक और प्रोटोकॉल औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होना चाहिए। लोकभवन को संवैधानिक मूल्यों – निष्पक्षता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के प्रचार–प्रसार का केंद्र भी बनाया जा सकता है। स्कूलों, महाविद्यालयों और युवा समूहों के लिए लोकभवन में स्थापित संविधान पार्क के अवलोकन के साथ ही संविधान–परिचर्चा, लोकतांत्रिक प्रशिक्षण और प्रेरणात्मक कार्यक्रम इस दिशा में प्रभावशाली पहल होंगे। साथ ही, समय–समय पर इस परिवर्तन की प्रभावशीलता का आकलन भी आवश्यक किया जाना चाहिए, ताकि यह देखा जा सके कि लोकभवन नाम के अनुरूप सेवा–व्यवहार, नागरिक संवाद और प्रशासनिक पारदर्शिता में वास्तव में सुधार हुआ है या नहीं। इस निगरानी में नागरिक समाज, मीडिया और विशेषज्ञ समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लोकभवन का सबसे बड़ा और सार्थक अर्थ यही होगा कि राज्यपाल का निवास अब महज़ सत्ता का प्रतीक न रहकर नागरिक अधिकारों, संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक विश्वास का केंद्र बन जाए। जनता में यह भाव उत्पन्न हो कि यह भवन उनकी अपेक्षाओं, समस्याओं और सुझावों के प्रति संवेदनशील है।

निष्कर्षतः राजभवन का नाम बदलकर लोकभवन करना निस्संदेह एक प्रगतिशील और स्वागतयोग्य कदम है, जो लोकतंत्र की जन–केंद्रित भावना को पुनःस्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण संकेत है। यह नाम तभी सार्थक होगा जब इसके अनुरूप सोच एवं कार्य–संस्कृति बदले, प्रशासनिक व्यवहार बदले और जनता से संवाद की प्रकृति बदले। लोकभवन वास्तविक अर्थों में तभी 'लोक' का भवन बनेगा, जब वह जनता के हितों, संवेदनशीलता और सहभागिता का केंद्र बनेगा। यदि इस पहल के साथ सुसंगत संस्थागत सुधार, पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक–सुलभ व्यवहार को मजबूती से अपनाया गया, तो यह कदम राजस्थान में लोकतांत्रिक चेतना को नई ऊँचाई देने वाली एक ऐतिहासिक उपलब्धि सिद्ध होगा।

– डॉ. कैलाश चन्द सैनी,
पूर्व मुख्य शोध एवं संदर्भ अधिकारी, राजस्थान विधान सभा, जयपुर

झील संरक्षण जागरूकता के लिए साइकिल यात्रा

- **फतेहसागर झील से आनासागर झील तक**
- **साइकिल कम्युनिटी के सदस्यों ने जोर शोर से भव्य स्वागत किया**

अजमेर। पर्यावरण संरक्षण एवं दैनिक जीवन में स्वास्थ्य के लिए साइकिल की उपयोगिता के उद्देश्य को लेकर उदयपुर साइकिलिंग क्लब के 8 सदस्यों की एक टीम अजमेर आया। जिसका अजमेर साइकिल कम्युनिटी के सदस्यों ने जोर शोर से भव्य स्वागत किया। प्रवक्ता राजेंद्र गांधी ने बताया कि उदयपुर फतहसागर झील से आना सागर झील तक साइकिल चलाते हुए निकले। करीब 500 किमी की साइकिल चला कर झीलों को प्रदूषण से बचाने के लिए आमजन को जागरूक किया। टीम में कुल 8 राइडर्स जिसमे 18 साल से लेकर 55 साल के राइडर्स थे। टीम में नितेश टाक, भवानी पांडिया, राजेंद्र शर्मा, प्रवीण शेखेडकर, सुधांशु माथुर, शांतनु साहू ,जितेन्द्र पटेल, गौरव सिखवाल शामिल थे। जिनका अजमेर पहुंचने पर साइकिलिंग कम्युनिटी एवं मॉर्निंग मॉस्किटर्स के सदस्यों ने भव्य स्वागत करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। साइकिल कम्युनिटी के अध्यक्ष ललित नागरानी एवं मॉर्निंग मास्किटर्स के अध्यक्ष डॉ अकरम ख़ान, मोनिल टाक, नितिन जैन, नरेंद्र सोलंकी, वेद प्रकाश, विजेंद्र, वेंकटेश, तरुण, कमलेश, लक्ष्मी नारायण सोनी, अक्षय, ललित कुमार जांगिड, अर्जुन सिंह, राजेंद्र गांधी, आशीष छाबड़ा, कपिल माहेश्वरी सहित अन्य सदस्यों ने माल्यार्पण किया एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया।

लावारिश शवों की अस्थियों का विसर्जन

अलवर। भिवाड़ी की श्री राम सेवा समिति ने रविवार को मानवता और सेवा की मिसाल पेश करते हुए लावारिश शवों की अस्थियों का गढ़ गंगा में विसर्जन किया। समिति के सदस्य अल्प सुबह ही भिवाड़ी से रवाना होकर गढ गंगा पहुंचे और मंत्रोच्चार के बीच अनजान लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अस्थि विसर्जन के दौरान समिति के सदस्यों ने फूल–मालाओं और पवित्र जल के साथ धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए विधिवत विसर्जन प्रक्रिया पूरी की। समिति के प्रधान विनीत सिसौदिया ने बताया कि श्री राम सेवा समिति पिछले लंबे समय से भिवाड़ी में उन लोगों का अंतिम संस्कार करवाती आ रही है, जिनकी मृत्यु के बाद उनके परिजनों का पता नहीं लगता। इस स्थिति में पुलिस द्वारा समिति को सूचना दी जाती है और समिति के सदस्य सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करवाते हैं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को सम्मानजनक विदाई मिलनी चाहिए, चाहे उसके जीवन में कोई परिवार साथ रहा हो या नहीं।

पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य को लेकर चेकअप कैम्प

अलवर। पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य को लेकर पुलिस अधिक्षक सुधीर चौधरी चिन्तित है इसी को देखते हुए उन्होंने रविवार को मैडिकल चेकअप कैम्प का आयोजन पुलिस लाईन में आयोजित किया पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को रिजर्व पुलिस लाईन जिला अलवर मे पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियो के लिए डॉ. प्रदीप कथुरिया एमडी (होम्यो), डॉ. बी. लाल. लैबोरेट्री व टाईटन आई प्लस जिला अलवर के संयुक्त तत्वाधान में मेडिकल टीम द्वारा निःशुल्क मेडिकल हैल्थ चैकअप शिविर, परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिलें के पुलिस अधिकारी, कर्मचारी एवं जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मेडिकल टीम द्वारा पुलिसकर्मियों का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, बीपी, शुगर, ईसीजी, आई टेस्ट आदि का चैकअप किया गया। शिविर में पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियो द्वारा अपना हैल्थ चैकअप करवाया गया। डॉक्टर द्वारा पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियो को स्वास्थ्य के बारे मे परामर्श दिया गया। शिविर में डॉक्टरों की टीम ने पुलिसकर्मियों को स्वास्थ्य जागरूकता, तनाव प्रबंधन, खानपान, एवं फिटनेस से संबंधित मार्गदर्शन भी प्रदान किया। सभी जवानों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार आवश्यक चिकित्सीय परामर्श और दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई गईं। पुलिस जवानों का स्वास्थ्य और फिटनेस पुलिस विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण से न केवल कार्य क्षमता बढ़ती है बल्कि बीमारियों की रोकथाम में भी मदद मिलती है। पुलिस विभाग द्वारा आगामी दिनों में भी समय समय पर इस प्रकार के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित करते रहेंगे। ताकि पुलिसकर्मी स्वस्थ, सुरक्षित और सक्षम रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

कल्याणपुरा में बीज निगम के कृषि फार्म से लीज धारक ने लाखों की राशि में हरे पेड़ों को काटा

- **कृषि फार्म को नियम विरुद्ध अन्य किसानों को सबलेट भी किया हैं**
- **कृषि विभाग के शासन उप सचिव ने बीज निगम के निदेशक को जांच का आदेश जारी किए**

माण्डलगढ़। माण्डलगढ़ उपखण्ड क्षेत्र के कल्याणपुरा में स्थित राजस्थान स्टेट सीडस कार्पोरेशन लिमिटेड के कृषि फार्म से लाखों की राशि के बड़े बड़े हरे वृक्षों को काट कर बेच देने का मामला सामने आया हैं। ओर फार्म पर कई अनियमितता भी अधिकारियों की जा रही हैं।इस मामले को लेकर कृषि फार्म के पूर्व ठेकेदार ने कृषि मंत्री को शिकायत कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की माँग की हैं। कृषि मंत्री को लव जिन्दल द्वारा प्रेषित शिकायत में बताया कि सरकार अधीनस्थ बीज निगम भीलवाडा की कृषि भूमि रकबा 46.7087 हैक्टेयर ठाम कल्याणपूरा तहंसील माण्डलढगढ जिला भीलवाडा में स्थित हैं। कृषि भूमि में लगे पेड़ों को संवेदक ओर विभागीय अधिकारियों ने मिली भगत कर अवैध रूप से चोरी छुपे काटकर खुर्द बुर्द कर दिया गया हैं।

भीलवाड़ा बीज निगम द्वारा 3 वर्ष के लिए गोपालपुरा निवासी छीतरलाल जाट को 20 जून 2024 से 20 जून 2027 तक लीज पर आंवटित किया हुआ है।उक्त कृषि फार्म की भूमि पर किसानों द्वारा फसल बीज उत्पादन किया जाता है। लीज अवधिं के दौरान लीज संवेदक ओर किसानों के उत्पादित बीज को बीज निगम द्वारा खरीद किया जाता हैं। लीज संवेदक छीतरलाल जाट द्वारा कृषि फार्म के करीब 218 पेड़ जो बबूल , शीशम , नीम ओर अन्य छायादार पेडों को 15 मई 2025 को रात्रि के अंधेरे में कटवा कर लाखों की राशि मे बेच दिया हैं। ओर काटे गए पेड़ों के अवशेष को जेसीबी मशीन से उखाड़ दिया गया। जिससे भूमि का स्वरूप बिगड़ने के साथ पर्यावरण को भी नुकशान पहुंचाया गया हैं। शिकायत में जिंदल ने बताया कि विभाग द्वारा उक्त कषि भूमि के लीज आवंटन के दौरान ड्रोन कैमरे से सम्पूर्ण कृषि फार्म की वीडियोग्राफी करवायी गई थी। जिसमें सम्पूर्ण कृषि भूमि पर लगे पेड़ पौधों एव अन्य संरचनाओ की सम्पूर्ण रिकॉर्डिंग विभाग के पास मौजूद है। लव जिंदल ने पत्र में आरोप लगाया कि भीलवाड़ा बीज निगम को इस मामले की कई बार शिकायत की गई लेकिन अधिकारियों द्वारा कार्रवाई को गोलमाल कर उच्चाधिकारियों को गुमराह किया गया हैं। वहीं लीज धारक ने कृषि फार्म में भंवरलाल किसान को नियमविरुद्ध सबलेट भी किया हुआ हैं। इस शिकायत को कृषि विभाग जयपुर के शासन उप सचिव नवरत्न कोली ने प्रदंध निदेशक, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड जयपुर को पत्र लिख कर तथ्यात्मक जाँच के आदेश दिए है और की गई करवाई की रिपॉर्ट मांगी है। वहीं भीलवाड़ा बीज निगम के अधिकारियों ने लव जिंदल की शिकायत ओर आरोप को बे बुनियाद बताया हैं।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

सोमवार 8 दिसम्बर, 2025

पौष मास, कृष्ण पक्ष, चतुरथी तिथि, सोमवार, विक्रम संवत 2082, पुष्य नक्षत्र रात्रि 2:53 तक, ब्रह्म योग सायं 5:01 तक, बालव करण सायं 4:04 तक, चन्द्रमा आज कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य–वृश्चिक, चन्द्रमा–कर्क मंगल–वृश्चिक, बुध–वृश्चिक, गुरू–मिथुन, शुक्र–वृश्चिक, शनि–मीन, राहु–कुम्भ, केतु–सिंह राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि 2:53 तक है। महापात योग प्रातः 9:49 से दिन 3:35 तक है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः अमृत सूर्योदय से 8:25 तक, शुभ 9:43 से 11:04 तक, चर 11:36 से 2:54 तक, लाभ–अमृत 2:54 से सूर्यास्त तक।

राहूकालः 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदये 7:08, सूर्यास्त 5:29 तक

मेष
घर–परिवार में सुख–सुविधाओं में वृद्धि होगी। परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज अनावश्यक धन खर्च हो सकता है।

वृष
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

मिथुन
घर–परिवार में चल रही स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल–आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा।

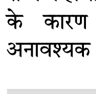

तुला
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

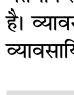

वृश्चिक
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

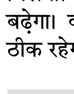

धनु
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। अनावश्यक धन खर्च होगा।

मकर
परिवार में शुभ–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आपसी सहयोग–समन्वय से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आज व्यावसायिक आर्थिव मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कुंभ
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अस्त–व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी और कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।